

लोक प्रशासन में
उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार
**Prime Minister's Awards for
Excellence in Public Administration**
2009 - 2010



सत्यमेव जयते

प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार

Department of Administrative Reforms and Public Grievances
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Government of India

Initiative - Success Story of Malkapur 24x7 Water Supply Scheme

- Name of the Awardees -
1. Mr. Rajendra Ganeshlal Holani
Chief Engineer, Maharashtra Jeevan Pradhikaran, Region Aurangabad
 2. Mr. Sadanad Kashinath Bhopale,
Section Engineer
 3. Mr. Sunil Yashwant Basugade,
Section Engineer
 4. Mr. Uttam Pandurang Bagade,
Section Engineer
Office of the Executive Engineer,
Maharashtra Jeevan Pradhikaran,
Works Division, Karad,
District: Satara.

Malkapur town piped water supply scheme, commissioned in 1988 was envisaged to supply 40 liters per capita per day (LPCD) on the basis of an estimated population growth of 14,000 by 2010. But the town's population increased 50% more than the estimated growth and 10 years earlier than the projection. This resulted in poor and unreliable supply of water and untimely service. To overcome this problem, a distribution network was designed using "Water Gems" software ensuring '24x7 availability'. The transparent process of manufacture of pipes involving the village Panchayat-members ensured quality. The methodology regarding the resin to be used for manufacturing these pipes was tendered and accredited by an international agency. Third party inspection, an essential pre-requisite as per the tender, was carried out and certified by an inspection agency. Thus, it was ensured that the pipes used for connections conformed to relevant ISO standards. Similarly, Automatic Meter Readers (AMR meters) used in

the project too were third-party inspected. Laying the pipelines was properly planned, and phased zone-wise execution was completed in time. Local residents and stakeholders including the public representatives undertook a special drive to convince people to fix proper stop-cocks. Progressive / telescopic water tariff system was introduced to curb excessive usage of water.

This initiative improved the delivery time and services of water supply. It also contributed to good quality of water-delivery as a result of pressurized water throughout the day and night. 30% reduction in wastage of water was ensured with telescopic tariff structure and with gradual decrease in the number of hours of water supply from 19-20 hours to 13-14 hours per day. Simplification of billing procedure with AMR type meter installation ensured that reading could be taken remotely by driving through the streets using radio-frequency driven hand-held devices. As the pumping of water to the water tank on terraces was not required, use of electricity was remarkably reduced leading to energy conservation and reduction in pollution, to an estimated extent of 450 tons of carbon dioxide in the atmosphere. The system of automation using GSM technology reduced the cost of operation and eliminated the requirement of pump operators.

पहल - मल्कापुर 24x7 जल आपूर्ति स्कीम की सफलता की कहानी

- पुरस्कार विजेताओं का नाम -
1. श्री राजेंद्र गणेशलाल होलाणी
मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,
क्षेत्र औरंगाबाद
 2. श्री सदानंद काशीनाथ भोपाले,
सेक्शन अभियंता
 3. श्री सुनील यशवन्त बासुगडे,
सेक्शन अभियंता
 4. श्री उत्तम पांडुरंग बागडे,
सेक्शन अभियंता,
कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,
कार्य प्रभाग, कराड़,
जिला: सतारा

1988 में शुरू की गई मल्कापुर कस्बे के लिए नलों के जरिए जल आपूर्ति की योजना में सन 2010 तक 14000 की अनुमानित जनसंख्या वृद्धि के आधार पर 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) जलापूर्ति की परिकल्पना की गई थी। लेकिन कस्बे की आबादी अनुमानित समय से 10 वर्ष पहले ही अनुमानित वृद्धि से 50 प्रतिशत अधिक बढ़ गयी। इसके परिणामस्वरूप जलापूर्ति सेवा खराब और अस्त-व्यस्त हो गई। इस समस्या से निपटने के लिए “वाटर जेम्स” सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एक डिस्ट्रिब्यूशन नेटवर्क डिजाइन किया गया ताकि चौबीसों घंटे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ग्राम पंचायत के सदस्यों को शामिल करके पाइप बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया, इससे पाइपों की गुणवत्ता सुनिश्चित हुई। इन पाइपों के निर्माण के लिए प्रयुक्त की जाने वाली राल से संबंधित प्रणाली के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी और इस प्रणाली को एक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी से प्राप्त किया गया था। तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण, ठेके की एक आवश्यक पूर्व शर्त थी, इसके अनुसार एक निरीक्षण एजेंसी द्वारा इन पाइपों की जांच करायी गई और इन्हें प्रमाणित कराया गया। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया कि

कनेक्शन में उपयोग होने वाले पाइप आई.एस.ओ. के तत्संबंधी मानकों के अनुरूप हों। इसी प्रकार परियोजना में उपयोग होने वाले ऑटोमेटिक मीटर रीडरों (एएमआर) की भी तीसरे पक्ष से जांच करायी गई। पाइप लाइन बिछाने की सुव्यवस्थित योजना बनायी गई और चरणबद्ध तरीके से अलग क्षेत्रों में पाइप बिछा कर यह कार्य समय पर पूरा कर लिया गया। स्थानीय लोगों, स्टैकहोल्डरों और जनप्रतिनिधियों ने विशेष अभियान चलाकर लोगों को सही टॉटियां लगाने के लिए समझाया। पानी के आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए वृद्धिगत/टेलीस्कोपिक जल शुल्क प्रणाली शुरू की गई।

इस पहल से जलापूर्ति सेवा और समय दोनों में सुधार हुआ। दिन रात अच्छे दबाव के साथ पानी की सप्लाई से जलापूर्ति की गुणवत्ता भी बेहतर हो गई। टेलीस्कोपिक शुल्क ढांचे और प्रतिदिन जलापूर्ति के 19-20 घंटों को क्रमिक रूप से घटाकर 13-14 घंटे करने से पानी की बर्बादी में 30 प्रतिशत की कमी आई। एएमआर टाइप मीटर लगा कर बिलिंग प्रक्रिया आसान बनाई गई और यह सुनिश्चित किया गया कि मीटर रीडर अपने हाथ में पकड़े हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी से चलने वाले छोटे से उपकरणों के जरिए दूर से ही रीडिंग ले लें। अब छतों पर रखी गई टैंकियों तक पानी पम्प करने की आवश्यकता नहीं रह गई थी, बिजली की खपत काफी कम हो गई और वातावरण में कार्बन डाइआक्साइड के उत्सर्जन में लगभग 450 टन तक की कमी आने से प्रदूषण में कमी हुई। ऑटोमेशन प्रणाली में जीएसएम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया, इससे संचालन लागत में कमी आई और पम्प ऑपरेटरों की आवश्यकता नहीं रही।